



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 15 सितम्बर, 1987/24 माघपद, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

FINANCE DEPARTMENT

(FINANCE COMMISSION CELL)

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 8th September, 1987*

No. Fin. Comm. B (10) 1/85.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order, to substitute the following, appearing in para 4.5 Reconciliation of Accounts of the Accounting procedure governing the implementation of the Himachal Pradesh Government Employees Group Insurance Scheme, 1984 to facilitate the proper checking and maintenance of accounts:—

“The Drawing and Disbursing Officer will reconcile the amounts quarterly with the Treasury Officer, credited/paid to from the Savings Fund/Insurance Fund in respect of the establishment of his office with the figures maintained in the office of the Treasury Officer of the district concerned.

The Treasury Officer, after reconciliation, would furnish the details to the Senior Deputy Accountant General (A&E), H. P., who would also reconcile the same with the accounts maintained by him in his office.”

Sd/-  
Financial Commissioner-cum-Secretary.

## सहकारी विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 7 सितम्बर, 1987

संख्या कोप-ई (11)21/74-4.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1968 (3 अप्रैल 1969) की धारा 109 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों जिनके द्वारा उन्हें सशक्त किया गया है, का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सहकारी नियम, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो पहले हिमाचल प्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई, 1987 में अधिसूचित किए गए थे:—

### THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) RULES, 1987

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Rules, 1987.

(2) These shall come into force at once.

2. *Amendment of rule 38.*—For the existing sub-rule (3) of rule 38 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Rules, 1971, the following sub-rule (3) shall be substituted, namely:—

“(3) The term of the Managing Committees constituted under sub-rule (1) shall be —

- |  |                 |
|--|-----------------|
| (a) in relation to Primary Societies   | .. 2 years;     |
| (b) in relation to Secondary Societies | .. 3 years; and |
| (c) in relation to Apex Societies      | .. 4 years;     |

Provided that the out-going managing committee shall, unless the State Government otherwise directs, continue to function till another managing committee is constituted under these rules:

Provided further that no person shall be eligible to hold office of President or Vice-President or elected member of the Managing Committee continuously for more than two terms unless a period of two years has elapsed after the expiry of the term of the Managing Committee in which he last hold office of President or Vice-President or elected member.

By order,  
S. S. SIDHU,  
Commissioner-cum-Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 9 सितम्बर, 1987

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 15/86.—क्योंकि श्री लाल चन्द को ग्राम पंचायत खंगसर, जिला लाहौल-स्पीति के प्रधान पद से समसंख्यक आदेश दिनांक 2-12-86 के अन्तर्गत हटाने में निष्कासित किया गया था क्योंकि उन्होंने

बहसियत प्रधान, ग्राम पंचायत गुन्दला, श्री रोशन लाल पुत्र श्री टश। राम को 6000.00 रुपये में कम वार्षिक आय का गलत प्रमाणपत्र दिया था;

क्योंकि उक्त श्री लाल चन्द ने सरकार को 28-4-87 को निष्कामन आदेशों को समाप्त करने के लिये प्रार्थनापत्र दिया था और क्योंकि जिलाधीश, लाहौल-स्पिति में प्राप्त रिपोर्ट के दृष्टिगत तथा श्री लाल चन्द की लोक प्रियता को देखते हुये निष्कर्ष का दण्ड ज्यादा कड़ा पाया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 54(4) के अन्तर्गत 2-12-86 को जारी आदेशों को समाप्त करने का आदेश देते हैं वहां श्री लाल चन्द को भविष्य में इस तरह के मामलों में विशेष सावधानी बरतने का भी सहष आदेश देते हैं।

हस्ताक्षरित/-  
अवर सचिव।

